(ख) कितने कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ग) जिन कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं उनके लिए क्या प्रबन्ध करने का विचार है और कब तक ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने अधिकारियों को कोई ज्ञापन दिया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की पटना शाखा में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 226 है ।

(ख) और (ग). रिजर्व बैंक ने पटना में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (अनुरक्षण कर्मचारियों) के लिए 10 फ्लेटों की व्यवस्था कर रखी है । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, राज्य सरकार और समाचार-पत्रों में विज्ञापन के जरिए अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी, रिजर्व बैंक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने के लिए पटना में भूमि प्राप्त नहीं कर सका है । उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं । उपयुक्त भूमि प्राप्त होते ही रिजर्व बैंक अतिरिक्त क्वार्टर बनाने के लिए कदम उठायेगा ।

(घ) रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के सम्बन्ध में, रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के पास कर्मचारी संघ का कोई ज्ञापन नहीं है ।

(ङ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

दिल्ली के कालेजों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये प्रवेश

6472. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुछ विद्यार्थियों को दिल्ली के कालेजों में प्रवेश देने से इन्कार कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) कालेजों में उनके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार सभी अनुसूचित जाति/कबीलों के विद्यार्थी जिन्होंने दाखिला मांगा था और जो 5 प्रतिशत अंकों की छूट सहित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते थे, दाखिल कर लिये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Seizure of Forged Dollars in Coimbatore

6473. SHRI M. M. JOSEPH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether recently any arrests were made in Coimbatore in regard to the seizure of forged American dollar notes ; and

(b) if so, the steps taken by Government against the culprits ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) and (b). The information is being collected from the State Government of Tamil Nadu and will be laid on the Table of the House as soon as received.

Credit facilities to Sugar Industries

6474. SHRI LAKSHMINARAYANAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Central Government have given some credit facilities to the Sugar factories all over the country ; and

(b) if so, the number of factories which availed of such a facility and of those who did not, and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): (a) Government have NOT given any credit facilities to Sugar factories themselves. Sugar factories in the country are availing credit facilities from Financial Institutions and Banks.

(b) The question does not arise in view of the reply to part (a).

पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

6475. श्री राम चन्द्र विकल : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काका कालेलकर के सभापतित्व में नियुक्त पिछड़े वर्ग आयोगों की मुख्य सिफारिशों को इस बीच लागू कर दिया गया है ;

(ख) अब कौन सी मुख्य सिफारिशें लागू की जानी हैं ; और

(ग) उक्त आयोगों की किन-किन सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही 3 सितम्बर, 1956 को लोक सभा के पटल पर रखे गये ज्ञापन में स्पष्ट कर दी गई थी। लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5138 दिनांक 16 जुलाई, 197 के उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस आयोग की जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, वे पिछड़ेपन के लिये कसौटी निश्चित करने के बारे में थी। आयोग ने अपने बहुमत की सिफारिश में सुझाव दिया था कि "अन्य पिछड़े वर्गों" का निश्चय करने के लिए कसौटी जाति होनी चाहिए। भारत सरकार ने इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार किया था और 1961 में यह निर्णय लिया था कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं बनाएगी और उसने "अन्य पिछड़े वर्गों" का निश्चय करने के प्रश्न को सम्बन्धित राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया था। उसके साथ-साथ राज्य सरकारों को सलाह दे दी गई थी कि वे इस मामले में जाति के स्थान पर आर्थिक कसौटी को अपनायें।

Completion of bridge over the Ganges at Jhunsi, Allahabad

6476. SHRI V. N. P. SINGH: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the initial target date for completion of bridge over the Ganges at Jhunsi, Allahabad;

(b) the reasons for delay; and

(c) when the bridge is now proposed to be completed?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): (a) March 1972.

(b) and (c). Slow progress on the part of the contractor, modification required to be made in the design of foundations due to deep clayey strata met with in some of the foundations and increase in the scope of work by the addition of one span. Taking these factors into account, the bridge is likely to be completed by June 1975.

Translation work given to translating agencies by C. S. T. T.

6477. SHRI V. N. P. SINGH: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) the total number of books given for translation to translating agencies by the Commission for Scientific & Technical Terminology during the last three years;

(b) the total amount paid to these agencies;

(c) the number of books remaining to be translated and published even after the expiry of the time given by the proprietors of the books; and

(d) the amount of royalty paid to the